

सरकार ने मंत्रालय के व्यय हेतु उच्च रपिपोर्टिंग सीमा का प्रस्ताव रखा

प्रलमिस के लिये:

लोक लेखा समिति, नई सेवा और सेवा के नए साधन, अनुदान की अनुपूरक मांग, सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, नयितरक और महालेखा परीक्षक

मेन्स के लिये:

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई वित्तीय सीमाएँ, वित्तपोषण सीमा बढ़ाने के संभावित लाभ और कमियाँ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

संसद की लोक लेखा समिति ने हाल ही में सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा 'नई सेवा' और 'सेवा के नए उपकरणों' पर खर्च के लिये वित्तीय सीमा बढ़ाने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

- वित्तीय सीमा में यह प्रस्तावित संशोधन आज़ादी के बाद चौथी बार है। अंतिम संशोधन वर्ष 2005 में हुआ लेकिन वर्ष 2006 में लागू हुआ।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई वित्तीय सीमाएँ क्या हैं?

- **नई सेवा और सेवा के नए उपकरण:**
 - नई सेवा (NS) एक नए नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय को दर्शाती है जो पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, जिसमें नई गतिविधियाँ या नविश [संवधान का अनुच्छेद 115(1)(a)] शामिल हैं।
 - सेवा का नया साधन (New Instrument of Service- NIS) मौजूदा नीति के उल्लेखनीय विस्तार से उत्पन्न अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण व्यय को संदर्भित करता है।
- **नई सीमा:**
 - 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए के बीच के व्यय के लिये संसद को रपिपोर्ट करना अनिवार्य है, लेकिन पहले से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
 - पूर्व संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता केवल तभी होती है जब खर्च 100 करोड़ रुपए से अधिक हो।
 - 'सेवा के नए उपकरण' के लिये रपिपोर्टिंग सीमा मूल वनियोग का 20% या 100 करोड़ रुपए तक, जो भी अधिक हो, तय की गई है।
 - मूल वनियोग के 20% से अधिक या 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशियों के लिये संसद की मंजूरी अनिवार्य हो जाती है, जो समान अनुदान अनुभाग के भीतर बचत के अधीन है।

नोट: पहले, सीमा 10 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए के बीच बहुत कम थी और व्यय की लगभग 50 वस्तुओं में मूल्य भिन्न था।

वित्तपोषण सीमा बढ़ाने के संभावित लाभ और हानियाँ हैं?

- **संभावित लाभ:**
 - **अनुपूरक मांगों की आवृत्ति में कमी:** हाल के वर्षों में, PAC और CAG ने उचित रपिपोर्टिंग या अनुमोदन के बिना पूरक खर्च में वृद्धि को उजागर किया है।
 - खर्च की वित्तीय सीमा बढ़ाने से अनुदान की अनुपूरक मांगों की आवश्यकता कम हो जाएगी। यह बजटीय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।
 - **प्रशासनिक बाधाएँ कम हुईं:** वित्तीय सीमाओं में संशोधन अपेक्षाकृत छोटे व्ययों के लिये अनुमोदन प्राप्त करने से जुड़ी नौकरशाही बाधाओं को कम करता है।

- यह सरकारी विभागों और एजेंसियों के भीतर नरिणय लेने एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में दक्षता को बढ़ावा देता है।
- **आर्थिक विकास के लिये अनुकूलन:** साल-दर-साल 6-7% की अनुमानित **GDP वृद्धि दर** के साथ, आने वाले वर्षों में बजट का आकार काफी बढ़ने का अनुमान है।
- वित्तीय सीमाएँ बढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि बजट बढ़ती अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को समायोजित कर सकता है।
- **संभावित कमियाँ:**
 - **बजटीय अनुशासन को कमजोर करना:** यदि पर्याप्त नगरानी तंत्र मौजूद नहीं है, तो यह जोखिम है कि धन के दुरुपयोग या गलत आवंटन के लिये उच्च वित्तीय सीमाओं का फायदा उठाया जा सकता है।
 - इससे भ्रष्टाचार या फजूलखर्ची की घटनाएँ हो सकती हैं।
 - इसके परिणामस्वरूप बजटीय अतिवृद्धि या घाटा हो सकता है, जिससे समग्र **राजकोषीय स्थिति** प्रभावित हो सकती है।
 - **जवाबदेही की कमी:** मंत्रालयों और विभागों के लिये बढ़ी हुई वित्तीय स्वायत्तता के परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन के उपयोग के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है।
 - इससे व्ययों पर नज़र रखना और यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि वे इच्छित उद्देश्यों के साथ संरेखित हों।
 - **संसदीय नरीक्षण पर प्रभाव:** वित्तीय सीमाएँ बढ़ाने से सरकारी खर्चों पर संसदीय जाँच की आवृत्ति कम हो सकती है, जिससे सार्वजनिक वार्ता और नरीक्षण के अवसर सीमित हो सकते हैं।
 - यह पारदर्शी शासन के लिये आवश्यक नियंत्रण और संतुलन को कमजोर कर सकता है।

लोक लेखा समिति क्या है?

- **परिचय:** लोक लेखा समिति **भारत की संसद** द्वारा स्थापित संसद के चयनित सदस्यों से बनी एक इकाई है, जिसका प्राथमिक कार्य भारत सरकार के राजस्व और व्यय की जाँच करना है।
 - इसका प्राथमिक दायित्व जाँच के दौरान CAG की सहायता से **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक** द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों का ऑडिट करना है।
 - विशेष रूप से, इसके किसी भी सदस्य को सरकार में मंत्री पद संभालने की अनुमति नहीं है।
- **सदस्य:** PAC में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
 - सदस्यों को **एकल हस्तांतरणीय वोट** के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा वार्षिक तौर पर चुना जाता है।
 - अध्यक्ष की नियुक्ति **लोकसभा अध्यक्ष** द्वारा की जाती है और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
 - चेयरपर्सन मुख्यतः वपिक्षी दल से होता है।

अनुच्छेद 115 के तहत अनुदान के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

- **अनुपूरक अनुदान:**
 - **उद्देश्य:** चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रत्याशित व्यय उत्पन्न होने और किसी विशिष्ट सेवा के लिये आवंटित बजट अपर्याप्त होने की दशा में अनुपूरक अनुदान की मांग की जा सकती है।
 - **अनुमोदन प्रक्रिया:** सरकार वित्तीय वर्ष के अंत से पहले आवश्यक अतिरिक्त धनराशिके **अनुमोदन** के लिये संसद के समक्ष अनुमान प्रस्तुत करती है।
- **अतिरिक्त अनुदान:**
 - **उद्देश्य:** चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित सेवाओं के अतिरिक्त **किसी नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता** पड़ने की दशा में इस अनुदान की मांग की जा सकती है।
 - **अनुमोदन प्रक्रिया:** अनुपूरक अनुदान के समान सरकार वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अनुमोदन के लिये संसद के समक्ष अतिरिक्त धन राशिका अनुमान प्रस्तुत करती है।
- **अतिरिक्त अनुदान:**
 - **उद्देश्य:** किसी सेवा पर वास्तविक व्यय मूल रूप से बजट और संसद द्वारा स्वीकृत धन राशि से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त अनुदान की मांग की जा सकती है।
 - **अनुमोदन प्रक्रिया:** उक्त दो अनुदान के अनुमोदन प्रक्रिया के विपरीत, **अतिरिक्त अनुदान चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है।** वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय संसद में विचार हेतु "अतिरिक्त अनुदान की मांग" प्रस्तुत करते हैं।
 - अतिरिक्त अनुदान की मांगों को मतदान के लिये लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की नमिनलिखित में से कौन-सी वधियाँ हैं? (2012)

1. संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना।
2. वित्तियोग वधियक पारति होने के बाद ही भारत की संचति नधिसे धन की नकिासी।
3. अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान के प्रावधान।
4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा व्यापक आर्थिक पूर्वानुमानों और व्यय के वरिद्ध सरकार के कार्यक्रम की आवधकि या कम-से-कम मध्य-वर्ष की समीक्षा करना।
5. संसद में वित्त वधियक पेश करना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

दवियांगजनों के लयि आवगमन की सुगमता

प्रलिमिंस के लयि:

[केंद्रीय लोक नरिमाण वभिाग](#), [दवियांगजन अधकिार अधनियिम, 2016](#), [सुगमय भारत अभयिान](#)

मेन्स के लयि:

दवियांगजनों के लयि समावेशति और समान अधकिारों को बढ़ावा देने का महत्त्व, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [केंद्रीय लोक नरिमाण वभिाग](#) ने सार्वजनकि भवनों में दवियांगजनों (PwD) के लयि आवगमन में सुधार करने हेतु कदम उठाए। [दवियांगजन अधकिार अधनियिम, 2016](#) के प्रावधानों के बावजूद दवियांगजनों से संबंधति चुनौतयिँ बनी हुई हैं जसिके कारण CPWD ने भवनों में आवगमन की सुगमता मानकों का अनुपालन सुनिश्चति करने के लयि सुधारात्मक उपायों का कारयान्वन कयि।

दवियांगजन अधकिार (RPwD) अधनियिम, 2016 क्या है?

■ परिचय:

- RPwD अधनियिम, 2016, [दवियांगजन अधकिार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय](#) का अनुसमर्थन करता है जसिका अनुमोदन भारत द्वारा वर्ष 2007 में कयि गया था।
 - इस अधनियिम ने नःशिक्त व्यक्ती (समान अवसर, अधकिार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधनियिम, 1995 को प्रतसि्थापति कयि।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नःशिक्त अथवा दवियांगजन की संख्या लगभग 26.8 मिलियन थी जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% है।
- [राष्ट्रीय प्रतदिर्श सरवेक्षण कार्यालय](#) के आँकड़ों के अनुसार भारत में दवियांगजनों का प्रतशित भारत की कुल आबादी का 2.2% है।
 - NSSO के 76वें चरण, 2019 के अनुसार 1 वर्ष की अवधभिें प्रतति 1,00,000 लोगों में से 86 व्यक्तीदवियांग थे।

■ दवियांगता की वसितारति परिभाषा:

- इस अधनियिम में दवियांगता को एक वकिासशील और गतशील अवधारणा के आधार पर परिभाषति कयि गया है।
- RPwD अधनियिम, 2016 में दवियांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दयि गए जसिमें केंद्र सरकार द्वारा दवियांगता के और अधकि प्रकार शामिल कयि जाने का प्रावधान है।

■ अधकिार और हकदारी:

- अधनियिम के तहत उपयुक्त सरकारों को दवियांगजनों के लयि समान अधकिार सुनिश्चति करने का कारय सौपा गया है।
- अधनियिम के तहत बेंचमार्क दवियांगजनों (चालीस प्रतशित अथवा उससे अधकि दवियांगता वाला व्यक्ती) और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले लोगों के लयि उच्च शकिषा में आरक्षण (न्यूनतम 5%), सरकारी नौकरयिँ (न्यूनतम 4%) और भूमिका आवंटन

(न्यूनतम 5%) जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जाते हैं।

- 6 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिये नशुलक शिक्षा की गारंटी का प्रावधान किया गया है।
 - सरकार द्वारा वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को दवियांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।
- इस अधिनियम में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को दवियांग व्यक्तियों के लिये सुलभ बनाने, उनकी भागीदारी तथा समावेशन को बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- सार्वजनिक भवनों के संबंध में आदेश:
 - दवियांगजन अधिकार नयिम, 2017 का नयिम 15 केंद्र सरकार को दवियांग जनों के लिये सुगमता सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक भवनों के लिये दशिा-नरिदेश और मानक स्थापति करने का आदेश देता है।
 - इन मानकों में दवियांग जनों के लिये मानक नरिमति वातावरण, परविहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है।
 - सार्वजनिक भवनों सहित प्रत्येक प्रतिष्ठान को वर्ष 2016 के सामंजस्यपूर्ण दशिा-नरिदेशों के आधार पर इन मानकों का पालन करना होगा।
 - नयिम 15 में हाल के संशोधनों के अनुसार प्रतिष्ठानों को वर्ष 2021 के सामंजस्यपूर्ण दशिा-नरिदेशों का अनुपालन करने की आवश्यकता है, जिससे दवियांग जनों के लिये सुगमता सुनिश्चित हो सके।
 - व्यापक दशिा-नरिदेशों में दवियांग जनों के लिये रैंप, ग्रैब रेल, लिफ्ट और शौचालय जैसी विभिन्न सुगमता सुविधाओं वाली योजना, नविदिा एवं वशिष्टताओं को शामिल किया गया है।
 - दवियांग जनों के लिये समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सभी भवन योजनाओं को इन दशिा-नरिदेशों के अनुरूप होना चाहिये।
 - मौजूदा इमारतों को अभिगम मानकों को पूरा करने, दवियांग जनों के लिये बेहतर समावेशिता को बढ़ावा देने की दशिा में पाँच वर्ष के भीतर रेट्रोफिटिंग से गुजरना अनिवार्य है।

नोट:

- RPWD अधिनियम, 2016 में 21 अक्षमताओं में अंधापन, दृष्टि-बाधिता, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, श्रवण विकार/दोष (बहरा और सुनने में कठिनाई), चलन-संबंधी विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी (डिस्लेक्सिया), मल्टीपल स्केलेरोसिस, वाक् एवं भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सकिल सेल रोग, बहु-विकलांगता, तेजाब हमले से प्रभावित और पार्किंसंस रोग शामिल हैं।

दवियांगों के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य पहल क्या हैं?

- अद्वितीय अक्षमता पहचान पोर्टल
- दीन दयाल दवियांग पुनर्वास योजना
- दवियांग जनों को सहायक उपकरणों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता
- दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप
- दविय कला मेला 2023

सार्वजनिक भवनों में सुगमता की स्थिति

- सुगम भारत अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक भवनों, परविहन और वेबसाइटों में दवियांगजनों के लिये सुगमता को बढ़ावा देना है।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 48 शहरों में कुल 1,671 इमारतों में दवियांगजनों के लिये उनकी सुगमता के स्तर के आकलन हेतु एक्सेस ऑडिट किया गया।
- केंद्र को 1,484 इमारतों को दवियांगजनों के लिये अधिक सुलभ बनाने की दशिा में रेट्रोफिटिंग हेतु वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए।
 - प्रस्तावित रेट्रोफिटिंग परियोजनाओं में से 1,314 भवनों के लिये निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, जो पहुँच संबंधी चिंताओं को दूर करने में प्रगति का संकेत देता है।
- सरकार ने 2,839 राज्य सरकारी भवनों की पहचान की, जिनमें सुगमता में सुधार के लिये रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है, इस उद्देश्य हेतु राज्यों के संसाधनों से धन आवंटित किया गया है।

सार्वजनिक भवनों में पहुँच के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- PwD और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में स्थापित दशिा-नरिदेशों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2021 के नए दशिा-नरिदेशों को राज्य सरकारों से इसी तरह की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।
 - वशिलेषकों का कहना है कि किसी भी राज्य ने अभी तक अपने भवन उपनयिमों में सामंजस्यपूर्ण दशिा-नरिदेशों को शामिल नहीं किया है, जो पहुँच के मुद्दों को संबोधित करने में व्यापक विफलता का संकेत देता है।

